Testwale Current Affairs PDF

Current Affairs search results for: "FITCH"

1. [illegible] 2024 [illegible] 6% [illegible] 6.3% [illegible] (June 22, 2023)

Fitch-raises-India's-GDP-forecast-to-6.3%-from-6%-for-FY24

[illegible] **2023-24** [illegible] **6%** [illegible] **6.3%** [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- FY23 [illegible], [illegible] 7.2% [illegible] FY22 [illegible] **9.1%** [illegible]

[illegible]

- [illegible] 2023 [illegible] 6.1% [illegible]–[illegible]–[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

- [illegible] 6.3% [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

- [illegible] 2022 [illegible] ([illegible]) [illegible] 250 [illegible]

- [illegible] 2022 [illegible]

[illegible]

- रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कमोडिटी की कीमतों में नरमी और मजबूत ऋण वृद्धि पर सरकार के जोर से निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

- इसका अनुमान है कि धीमी मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे लाभ होगा, और परिवार भविष्य की कमाई और रोजगार के बारे में आशावाद बढ़ा रहे हैं।

आरबीआई की नीतिगत दरें और मुद्रास्फीति

- आरबीआई ने पूरे वर्ष नीतिगत दरों को 6.5% पर बनाए रखा है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति मई में 7.8% के शिखर से घटकर 4.3% हो गई है, जो आरबीआई के 2-6% के सहनशीलता बैंड के भीतर आ गई है।

भावी वित्तीय वर्षों के लिए विकास का पूर्वानुमान

- फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि 2024-25 और 2025-26 दोनों वित्तीय वर्षों के लिए विकास दर 6.5% होगी।

2. विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में अभी भी अधिक एफडीआई निवेश: इंड-रा रिपोर्ट (Dec. 29, 2022)

FDI investment still more in service sector than manufacturing sector: Ind-Ra report

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) द्वारा 28 दिसंबर 2022 को प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अभी भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और अधिकतम निवेश अभी भी सेवा क्षेत्रों में है ।

इंड-रा के अनुसार "मेक इन इंडिया" अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, एफडीआई प्रवाह अभी भी सेवा क्षेत्र के पक्ष में झुका हुआ है।"

इंड-रा का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार करने की तुलना में सेवा क्षेत्र में व्यवसाय करना कम जटिल है। शायद इसी कारण हैकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाला ज्यादातर एफडीआई ग्रीनफील्ड इनवेस्टमेंट नहीं है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच एफडीआई में **सेवा क्षेत्र** और **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** और हार्डवेयर की हिस्सेदारी क्रमशः 41.3% और 19.6% थी, जबकि **विनिर्माण** का हिस्सा केवल 25.4% था।

अप्रैल 2000 और मार्च 2014 के बीच, इस तरह के प्रवाह में सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हिस्सा क्रमशः 37% और 5.9% था, और विनिर्माण का हिस्सा 35.4% था।

अक्टूबर 2019 और मार्च 2022 के दौरान $146.7 बिलियन के कुल एफडीआई प्रवाह में से सिर्फ चार राज्यों ने एफडीआई का 83.0% आकर्षित किया, जिसमें **महाराष्ट्र 27.5%**, कर्नाटक 23.9%, गुजरात 19.1% और दिल्ली 12.4% था।

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2022 [illegible] **7**[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. [illegible] 2022 [illegible] 7% [illegible] (Nov. 11, 2022)

Moody's cuts India's economic growth projections to 7%

[illegible] 11 [illegible] 2022 [illegible] 2022 [illegible] 7.7 [illegible] **7** [illegible]

[illegible] 8.8 [illegible] 7.7 [illegible]

11 [illegible] 2022 [illegible] **2023-24** [illegible] 2022 [illegible] 7% [illegible]

[illegible] **2023** [illegible] **4.8** [illegible] **2024** [illegible] **6.4** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2023 [illegible] 2024 [illegible], 2024 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (11[illegible]) (11[illegible])

[illegible] / [illegible]	2022-23 [illegible]
[illegible]	7.0%
[illegible]	6.5%
[illegible]	6.8%
[illegible]	7.0% (2022)
[illegible]	6.8%
[illegible]	7.0%(2022)
[illegible]	6.9%
[illegible] ([illegible])	7.3%
[illegible] ([illegible])	5.7 %(2022)
[illegible]	6.9%
[illegible]	**7%**

4. [illegible] (Oct. 13, 2022)

[illegible]

रेटिंग्स इंडिया से कोई भी नई रेटिंग सेवा प्राप्त करने परतुरंत बंद करने को कहा है।

आरबीआई और सेबी की संयुक्त टीम द्वारा इसके कामकाज में कई कमियों के पाए जाने के बाद, **भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड** (सेबी) ने 6 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को निर्देश दिया था कि 6 महीने के भीतर अपने संचालन को बंद कर दे ।

भारत में क्रेडिट रेटिंग **एजेंसियों को सेबी** द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इक्रा(ICRA),फिच (Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स(Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय कंपनियां हैं जो सरकार या उन कंपनियों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करती हैं जो बाजार से पूंजी जुटाना चाहती हैं।
- क्रेडिट का अर्थ है ऋण और क्रेडिट योग्यता का अर्थ है कि धारकर्ता समय पर ऋण वापस करने में सक्षम है या नहीं और इसमें जोखिम का स्तर क्या है।
- रेटिंग एजेंसी धारकर्ता की वित्तीय ताकत और कमजोरी, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, उसके व्यवसाय के क्षेत्र आदि को देखती है और फिर अपनी राय व्यक्त करती है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी धारकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग देकर अपनी राय व्यक्त करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर रेटिंग दर्शाने के लिए लेटर ग्रेड(वर्णमाला) देती है । आम तौर पर एएए (AAA) रेटिंग ,धारकर्ता के लिए उच्चतम संभव रेटिंग है।
- इसका मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय में धारकर्ता के चूक का जोखिम बहुत कम है औरवह समय पर ऋण चुकाएगा।
- जोखिम जितना बड़ा होगा, रेटिंग उतनी ही कम होगी। अगर रेटिंग एजेंसी कर्जदार को **जंक रेटिंग** देती है तो इसका मतलब है कि चूक का जोखिम सबसे ज्यादा है।

रेटिंग के लाभ

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग धारकर्ता को ऋण देने में शामिल जोखिम के स्तर को निर्धारित करने में निवेशक/ऋणदाता की सहायता करती है।
- यह धारकर्ताओं की भी मदद करता है क्योंकि रेटिंग ब्याज दरों को प्रभावित करती है। यदि धारकर्ता को उच्चतम संभव रेटिंग दी गई है तो धारकर्ता को सबसे सस्ती संभव दरों पर ऋण मिलेगा। जैसे-जैसे रेटिंग घटती है जोखिम का स्तर बढ़ता है और साथ ही ब्याज दर भी।
- जिन कंपनियों को जंक रेटिंग दी गई है उन्हें बाजार से पैसा उधार लेना मुश्किल होता है और अगर कोई इसे ऋण प्रदान करने के लिए सहमत भी होता है तो ब्याज दर बहुत अधिक होती है।

5. सेबी ने बेंगलुरु स्थित ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बंद करने का आदेश दिया (Oct. 7, 2022)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों के उल्लंघन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया (Brickwork Ratings India) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही नियामक ने इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में भारत में अपना कारोबार समेटने का निर्देश दिया है. इसके अलावा एजेंसी पर कोई नया ग्राहक लेने की रोक भी लगाई गई है.

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने कई तरह के उल्लंघन किए हैं. नियामक ने कहा कि ब्रिकवर्क ने उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और साथ ही रेटिंग प्रदान करते समय सही तरीके से जांच-परख भी नहीं की.

आरबीआई और सेबी द्वारा ब्रिकवर्क की संयुक्त जांच में कंपनी के कामकाज में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांचों के निष्कर्षों में कथित उल्लंघनों में से कुछ भूषण स्टील, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, एस्सेल कॉरपोरेट रिसोर्सेज और डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संस्थाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के डिफ़ॉल्ट की मान्यता में देरी या विफलता थी, जबकि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन और गायत्री प्रोजेक्ट्स फर्मों की रेटिंग की समीक्षा करने में विफल रहे।

ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। **अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इक्रा(ICRA),फिच (Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग(Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।**

ब्रिकवर्क रेटिंग्स

यह 2007 में स्थापित किया गया था और केनरा बैंक ब्रिकवर्क्स रेटिंग के प्रमोटरों में से एक था।

इसका मुख्यालय: **बेंगलुरु**, कर्नाटक

प्रबंध निदेशक: **विवेक कुलकर्णी**

6. 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत रह जाएगी: यूएनसीटीएडी (Oct. 4, 2022)

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी/अंकटाड) की **व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022** के अनुसार, 2022 (जनवरी-दिसंबर अवधि) में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर **5.7%** रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार , भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर **2023 में घटकर 4.7% रह जाएगी।**

2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में **8.7% की** वृद्धि हुई थी और चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इसमें **13.5%** की वृद्धि हुई है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 30 सितंबर 2022 को अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को घटाकर **7% कर दिया था** ।

भारत की आर्थिक विकास दर को कम करने के लिए अंकटाड रिपोर्ट द्वारा उद्धृत मुख्य कारण प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण सरकार के पूंजीगत व्यय में अपेक्षित कमी है।

अंकटाड ने कहा कि उसे उम्मीद है कि 2022 में **दक्षिण एशिया क्षेत्र** का **4.9 प्रतिशत** की गति से विस्तार होगा

अंकटाड के अनुसार , 2022 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और 2023 में 0.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी ।

चीन की आर्थिक वृद्धि 2022 में **3.9 प्रतिशत** और 2023 में **5.3 प्रतिशत** की वृद्धि का अनुमान है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (3 अक्टूबर 2022 तक)

एजेंसी /संस्थान	2022-23 के लिए पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक	7.0%
विश्व बैंक	7.5%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	7.4%
एशियाई विकास बैंक	7.2%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6.8%
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस	7.7%
इंडिया रेटिंग	6.9%
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी)	7.3%
यूएनसीटीएडी(अंकटाड)	5.7%
ओईसीडी	6.9%
फिच रेटिंग	**7%**

यूएनसीटीएडी **(संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन)**

यूएनसीटीएडी 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।

इसकी स्थापना विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

यह **विश्व निवेश रिपोर्ट** भी जारी करता है।

मुख्यालय: **जिनेवा**, स्विट्जरलैंड

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

7. [illegible] 2022-23 [illegible] 6.9% [illegible] (Sept. 27, 2022)

[illegible] (**[illegible]**) [illegible] 2022-23 [illegible] **6.9%** **[illegible]** [illegible]

[illegible] 2023-24 [illegible] **5.7%** [illegible]

[illegible] (**[illegible]**) [illegible] 2022-23 [illegible] **7.3%** [illegible]

[illegible] Q3 2022 [illegible], 2023-24 [illegible] **6.5%** [illegible]

[illegible] 2022-23 [illegible] 7% [illegible]

[illegible] 2022-23 [illegible] **7.2%** [illegible]

2021-22 [illegible] **8.7%** [illegible] 2022) [illegible] **13.5%** [illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible] 16 [illegible] 1960 [illegible] 18 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 38 [illegible]

[illegible]

[illegible]: **[illegible]**

8. [illegible] 2022-23 [illegible] **7%** [illegible] (Sept. 22, 2022)

[illegible] (21 [illegible] 2022 [illegible] 2022 [illegible] 2022-23 [illegible] 2022 [illegible] 7.2% [illegible] 7% [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 7% [illegible]

[illegible] 7.8% [illegible] 7% [illegible]

[illegible] 1966 [illegible]

- [illegible] 2022 [illegible] 3.3 [illegible]

[illegible] **-**

[illegible] ;

- [illegible] **1966** [illegible]
- [illegible]
- [illegible] : **68**
- [illegible] : [illegible]

9. [illegible] 7% [illegible] (Sept. 21, 2022)

[illegible] 2023 [illegible] 7% [illegible]

[illegible] 20 [illegible] 2022 [illegible]

[illegible] **-**

- [illegible] 2022-23 [illegible] 8-8.5% [illegible] 2022 [illegible]
- [illegible] 2022-23 [illegible] **7.2%** [illegible]
- **2021-22** [illegible] **8.7%** [illegible]

10. [illegible] 2023 [illegible] 7% [illegible] (Sept. 16, 2022)

[illegible] **(2022-23)** [illegible] **7.8%** [illegible] **7%** [illegible]

[illegible] 2023-24 [illegible] **6.7%** [illegible]

[illegible] ([illegible] 2022) [illegible] **13.5** [illegible] , [illegible] 16.2% [illegible]

[illegible] -

[illegible] :

- [illegible]
- [illegible]

[illegible] :

- [illegible] 2022 [illegible] **2.4%** [illegible] **2023** [illegible] **1.7%** [illegible]
- [illegible]

[illegible] (16 [illegible] 2022 [illegible]) :

[illegible] / [illegible]	2022-23 [illegible]
[illegible]	7.2%
[illegible]	7.5%
[illegible]	7.4%

[illegible]	7.2%
[illegible]	6.8%
[illegible]	7.7%
[illegible]	6.9%
[illegible] (([illegible])	7.3%
[illegible]	6.4%
[illegible]	6.9%

[illegible] -

[illegible] :

[illegible] :-

- [illegible]

[illegible] :-

- [illegible] **19** [illegible] **1** [illegible] **1999** [illegible]
- [illegible] : [illegible]
- [illegible]